BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 3, July-September 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 एवं अध्यापक शिक्षा – मुद्दे, चुनौतियां एवं भविष्य के लिए सुझाव

डॉ० वीणा कुमारी
प्राचार्या
राजीव गांधी मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,धनबाद (झारखण्ड)

शोध सार :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली को समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्गठित करने का एक व्यापक प्रयास है। यह 34 वर्षों बाद लागू की गई एक क्रांतिकारी नीति है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और नवाचार-युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस नीति का एक प्रमुख पहलू अध्यापक शिक्षा है, जिसे शिक्षा प्रणाली का आधार माना गया है। अध्यापक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। भारत में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में असंगति, शिक्षण प्रक्रियाओं में पारंपरिक दृष्टिकोण, और शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास की कमी जैसी समस्याएं इसे प्रभावित करती रही हैं। NEP 2020 ने अध्यापक शिक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। चार वर्षीय एकीकृत B.Ed. कार्यक्रम, सतत व्यावसायिक विकास (CPD), बहु-विषयक दृष्टिकोण, और डिजिटल शिक्षा का समावेश जैसे प्रावधान इसे अधिक सुदृढ़ और प्रासंगिक बनाते हैं। इसके तहत, शिक्षकों को न केवल अपने विषय में विशेषज्ञ बनाया जाएगा, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीकी उपकरणों और नवाचारों के उपयोग में भी दक्ष किया जाएगा। यह नीति न केवल वर्तमान शिक्षण चुनौतियों को हल करने का प्रयास करती है, बल्कि भविष्य की शिक्षा आवश्यकताओं के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करती है। NEP 2020 में अध्यापक शिक्षा सुधार शिक्षा प्रणाली में बदलाव की नींव रखने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। इस आलेख में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं अध्यापक शिक्षा से जुड़े मुद्दे, चुनौतियों पर व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है साथ ही भविष्य के लिए सुझाव प्रस्तुत किया गया है ।

कुंजी शब्द : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अध्यापक शिक्षा, चार वर्षीय एकीकृत B.Ed. कार्यक्रम

❖ परिचय:

शिक्षा नीति किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली के विकास, नियमन और प्रबंधन के लिए तैयार की गई एक व्यापक योजना होती है। यह नीति शिक्षा के उद्देश्य, संरचना, कार्यान्वयन और मानकों को निर्धारित करती है जिससे समाज की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा किया जा सके **(कुमार,** 2020)। स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई, जिसका उद्देश्य समानता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था। इसे 1986 में संशोधित किया गया, और 1992 में इसकी समीक्षा की गई। इस नीति ने विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया

BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 3, July-September 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

और शिक्षा को सुलभ और सर्व-समावेशी बनाने का प्रयास किया। 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) को लागू किया गया, जिसने 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित किया **(कुमारी, 2020)**। यह नीति स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक व्यापक सुधार लाने का प्रयास करती है।

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा के तहत चौथे सतत विकास लक्ष्य (SDG4 - शिक्षा) को अपनाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 बनाई। इसे 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई। पिछली शिक्षा नीति 1986/1992 के बाद, लगभग 34 वर्षों तक उसी को अपनाया गया। इस दौरान कई बड़े बदलाव हुए, जिनमें 2009 का **मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम** शामिल है, जिसने सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का कानूनी आधार दिया **(स्मिथा, 2020)**। दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। हर देश अपनी शिक्षा प्रणाली के जरिए सतत विकास के लिए काम कर रहा है। प्रौद्योगिकी का हर क्षेत्र में प्रभाव बढ़ रहा है। भारत को एक **वैश्विक ज्ञान शक्ति** बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में समयानुसार नए और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। शिक्षा नीति में बदलाव के जरिए ही देश को एक विकसित राष्ट्र में बदला जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, पाठ्यक्रम और शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए समय-समय पर नीतियों को अद्यतन करना आवश्यक है।

❖ राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 में अध्यापक शिक्षा सम्बन्धी मुख्य प्रावधान :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की सिफारिश की गई है। यह नीति उच्च शिक्षा से जुड़े भाग II के अध्याय 15 में विस्तार से चर्चा करती है और इसमें 11 मुख्य बिंदु शामिल हैं। नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षकों को विषयवस्तु, शिक्षण विधि (पेडागॉजी), और व्यावहारिक प्रशिक्षण में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले।

1. शिक्षकों के निर्माण में अध्यापक शिक्षा की भूमिका

अगली पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों की एक टीम के निर्माण में अध्यापक शिक्षा की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें बहुविषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही, उन्हें बेहतरीन मेंटरिंग के माध्यम से मान्यताओं और मूल्यों का आदान-प्रदान भी आवश्यक है, ताकि वे अपने अभ्यास में इन्हें आत्मसात कर सकें **(दार और जान, 2023)** । इसके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अध्यापक शिक्षा और शिक्षण प्रक्रियाएं न केवल अद्यतन और प्रासंगिक हों, बल्कि भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, लोकाचार, और परंपराओं के साथ-साथ जनजातीय परंपराओं के प्रति भी जागरूकता हो।

BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 3, July-September 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

2. स्टैंड-अलोन टीईआई के खिलाफ कठोर कदम

उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित वर्मा आयोग (2012) ने स्टैंड-अलोन टीईआई के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता जताई, जो अत्यधिक शुल्क लेकर डिग्री प्रदान करते हैं। यह संस्थान शिक्षा के मानक और गुणवत्ता को नजरअंदाज कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और लापरवाही की वजह से शिक्षा में सुधार नहीं हो पा रहा है। इसलिए, इन संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि शिक्षक शिक्षा के उच्च मानकों को लागू किया जा सके और संस्थानों में सुधार लाया जा सके।

3. अध्यापक शिक्षा के मानदंडों का पुनर्गठन

अध्यापक शिक्षा में नैतिकता, विश्वसनीयता और उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए शिक्षक शिक्षा संस्थानों को कठोर मानकों का पालन करना होगा। इन्हें उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों को लागू करने के लिए उचित निरीक्षण और मूल्यांकन की आवश्यकता है। इसके तहत शिक्षक शिक्षा के संस्थानों में एकीकृत और बहुविषयक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया जाएगा। 2030 तक, केवल उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को ही मान्यता दी जाएगी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि होगी।

4. बहुविषयक दृष्टिकोण के साथ अध्यापक शिक्षा

अध्यापक शिक्षा में बहुविषयक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे शिक्षकों को व्यापक ज्ञान और कौशल प्राप्त होता है। यह उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा देने में सक्षम बनाता है। सभी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को समग्र और बहुविषयक संस्थानों में आयोजित किया जाना चाहिए ताकि शिक्षक अन्य विषयों से भी परिचित हों और उनका शिक्षण दृष्टिकोण व्यापक हो। इससे शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार होगा और वे छात्रों को अधिक प्रभावी तरीके से पढ़ा सकेंगे।

5. 2030 तक 4-वर्षीय बी.एड. की अनिवार्यता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक, 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम को स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बना दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञता के साथ-साथ शिक्षण पद्धतियों की गहरी समझ भी होगी। यह कार्यक्रम उन शिक्षकों को तैयार करेगा जो अपनी कक्षा में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही, यह कार्यक्रम छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा और शिक्षण में सुधार के लिए तैयार करेगा।

विशेषज्ञता और अनुभव का महत्व

शिक्षक शिक्षा संस्थानों में विशेषज्ञों की नियुक्ति आवश्यक होगी ताकि वे शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुभव और ज्ञान को साझा कर सकें। संस्थान को विद्यालयों के साथ मिलकर काम करने के लिए एक नेटवर्क बनाना

BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 3, July-September 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

होगा। यह नेटवर्क शिक्षकों को व्यवहारिक प्रशिक्षण और अन्य सहायक गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करेगा। इससे शिक्षकों को वास्तविक जीवन में शिक्षा देने की दिशा में मदद मिलेगी और उनका शैक्षिक कौशल विकसित होगा।

7. राष्ट्रीय परीक्षा के माध्यम से प्रवेश

शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में एकरूपता बनाए रखने के लिए प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से होगा। यह परीक्षा छात्रों की शैक्षिक योग्यता और विषय के ज्ञान का मूल्यांकन करेगी। इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल योग्य और उच्च मानक वाले छात्र ही शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश करें। इससे शिक्षा के गुणवत्ता मानकों में सुधार होगा और अध्यापक शिक्षा की प्रणाली को मजबूत किया जाएगा।

8. बहुविषयक दृष्टिकोण के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति

अध्यापक शिक्षा में बहुविषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भाषा शिक्षा, गणित, विज्ञान, आदि जैसे विषयों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इससे शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में विविधता और गहराई आएगी। यह शिक्षकों को व्यापक दृष्टिकोण और शिक्षण कौशल प्रदान करेगा, जिससे वे विभिन्न प्रकार के छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ा सकेंगे।

पीएच.डी. छात्रों के लिए शिक्षण अनुभव

पीएच.डी. छात्रों के लिए यह अनिवार्य किया जाएगा कि वे अपने शोध के दौरान शैक्षिक अनुभव प्राप्त करें। वे शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम, और मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुभव प्राप्त करेंगे, जो उनके शोध कार्य को अधिक प्रभावी बनाएगा। यह उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों के उन्नत ज्ञान से लैस करेगा, जिससे उनका शोध और भविष्य का शिक्षण करियर बेहतर होगा।

10. शिक्षकों के लिए सतत व्यावसायिक विकास

शिक्षकों के लिए सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम जारी रहेगा और इसे और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों को अपने कौशल में सुधार करने का अवसर मिलेगा। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वयम/दीक्षा जैसी तकनीकी प्लेटफार्मों का उपयोग करके आयोजित किए जाएंगे, जिससे अधिक शिक्षकों को कम समय में उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण प्राप्त होगा। यह उन्हें समय के साथ बदलते शैक्षिक मानकों के अनुरूप बनाए रखेगा।

11. शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय मेंटरिंग योजना

एक राष्ट्रीय मेंटरिंग योजना स्थापित की जाएगी, जिसमें वरिष्ठ और अनुभवी संकाय सदस्य शामिल होंगे। ये मेंटर शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए तैयार होंगे। इस योजना के तहत, शिक्षकों

BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 3, July-September 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

को दीर्घकालिक परामर्श और सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपने करियर में आगे बढ़ सकें। यह योजना विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए सहायक होगी जो अपनी कक्षाओं में सुधार लाने के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं।

❖ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में अध्यापक शिक्षा से जुड़े मुद्दे एवं चुनौतियां

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन और सुधार की दिशा निर्धारित की है, जिसमें अध्यापक शिक्षा की भूमिका विशेष रूप से प्रमुख है। इस नीति के आलोक में अध्यापक शिक्षा से जुड़ी प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ निम्नलिखित है-

1. **स्टैंड-अलोन संस्थानों का बंद होने का खतरा**: स्टैंड-अलोन शिक्षक शिक्षा संस्थान (टीईआई) जो केवल शिक्षक प्रशिक्षण पर केंद्रित हैं, अब संकट में हैं। इन संस्थानों का बंद होने का खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि इनमें गुणवत्ता और समग्रता की कमी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में इन संस्थानों के पुनर्गठन की आवश्यकता बताई गई है ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें और व्यापक पाठ्यक्रम का हिस्सा बन सकें। NEP के तहत, उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ जुड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके और इन संस्थानों को बहु-विषयक शिक्षा में स्थान मिल सके।
2. **गुणवत्ता युक्त अध्यापक शिक्षा का मुद्दा**: शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना आज की शिक्षा नीति का सबसे बड़ा मुद्दा है। वर्तमान में, कई शिक्षक शिक्षा संस्थान मानकों पर खरे नहीं उतरते, जिससे शिक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। NEP 2020 में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन इसे लागू करना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण संस्थानों, बेहतर पाठ्यक्रम और शिक्षकों के लिए लगातार पेशेवर विकास के अवसरों की आवश्यकता है। इसके बिना, छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा नहीं मिल सकती है।
3. **अध्यक्ष शिक्षा में फैला भ्रष्टाचार का मुद्दा**: शिक्षक शिक्षा में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या बन गई है, जो शिक्षा के स्तर को घटित करता है। विभिन्न सरकारी और निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बिना सही मानकों के प्रमाणपत्र दिए जाते हैं, जिसके कारण गुणवत्ता में गिरावट आती है। NEP 2020 में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाने की बात की गई है, लेकिन इसे रोकने के लिए ठोस निगरानी तंत्र और सख्त नीतियों की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रिया को लागू करना जरूरी है।
4. **चार वर्षीय पाठ्यक्रम की सार्थकता**: NEP 2020 के तहत, चार वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम की पेशकश की जा रही है, जो शिक्षकों को समग्र शिक्षा प्रदान करेगा। यह पाठ्यक्रम शिक्षकों को केवल विषय ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक विकास, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, आदि में भी दक्ष बनाएगा। हालांकि, यह बदलाव कई

BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 3, July-September 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

5. सवाल उठाता है, जैसे क्या यह पाठ्यक्रम हर शिक्षण संस्थान के लिए व्यावहारिक होगा और क्या इसे लागू करना आसान होगा। चार वर्षों में अधिक ज्ञान और प्रशिक्षण देने का उद्देश्य है, लेकिन इसके लिए आवश्यक संसाधन और योग्य प्रशिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
6. **एक वर्षीय बनाम चार वर्षीय पाठ्यक्रम का द्वंद्व**: शिक्षक शिक्षा में एक वर्षीय और चार वर्षीय पाठ्यक्रमों के बीच बड़ा द्वंद्व है। जहां एक वर्षीय पाठ्यक्रम में तेजी से प्रशिक्षित शिक्षक तैयार किए जाते हैं, वहीं चार वर्षीय पाठ्यक्रम अधिक व्यापक और गहरे प्रशिक्षण की संभावना प्रदान करता है। दोनों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल है, क्योंकि एक वर्षीय पाठ्यक्रम को समय की कमी और व्यावहारिक अनुभव की कमी का सामना करना पड़ता है, जबकि चार वर्षीय पाठ्यक्रम में समय और संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है। NEP 2020 में चार वर्षीय पाठ्यक्रम को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन इसे हर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
7. **निजीकरण का मुद्दा**: शिक्षक शिक्षा में निजीकरण का मुद्दा भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। निजी संस्थान लाभ की दृष्टि से शिक्षा प्रदान करने में अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। NEP 2020 में निजी संस्थानों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त मानक और निरीक्षण तंत्र की आवश्यकता है। हालांकि, निजीकरण को बढ़ावा देने से संसाधनों की उपलब्धता बढ़ सकती है, लेकिन यदि इसका सही तरीके से नियमन नहीं किया गया, तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट हो सकती है।

❖ भारत में अध्यापक शिक्षा के भविष्य के लिए सुझाव:

भारत में शिक्षा व्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा शिक्षक होते हैं, और उनकी शिक्षा का स्तर सीधे तौर पर छात्रों की सफलता से जुड़ा हुआ है। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में हाल के वर्षों में कई सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई है, जिनका उद्देश्य न केवल शिक्षक की क्षमता को बढ़ाना है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार लाना है **(मसीह,2023)**। वर्तमान में इस क्षेत्र में कई चुनौतियाँ जैसे, अव्यवस्थित पाठ्यक्रम, अभावग्रस्त बुनियादी ढांचा, भ्रष्टाचार, और संसाधनों की कमी हैं, जो अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर असर डालते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के अंतर्गत इन मुद्दों का समाधान करने का प्रयास किया गया है। हालांकि, इसके बावजूद कई ऐसे निजी सुझाव हैं, जो अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इन सुझावों में पर्याप्त फंडिंग, शिक्षा के निजीकरण पर नियंत्रण, स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति, और बुनियादी ढांचे में सुधार प्रमुख हैं। साथ ही, सरकारी और निजी संस्थानों के बीच सहयोग, शोध

BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 3, July-September 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

को प्रोत्साहित करना, और भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अध्यापक शिक्षा को सशक्त और प्रभावी बनाने के प्रयासों को गति दी जा सकती है।

1. **प्रयाप्त फंडिंग**: अध्यापक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। सरकार को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों और उनके पाठ्यक्रमों के लिए अधिक बजट आवंटित करना चाहिए। इससे संस्थानों को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, तकनीकी उपकरण, और प्रशिक्षकों के लिए बेहतर वेतन देने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, अध्यापक शिक्षा के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुदान का भी समुचित उपयोग किया जा सकता है, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।
2. **निजीकरण पर नियंत्रण**: अध्यापक शिक्षा के निजीकरण पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए ताकि लाभ के बजाय गुणवत्ता और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। निजी संस्थान अधिकतर मुनाफे के उद्देश्य से शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे कई बार शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। सरकार को निजी संस्थानों के लिए कड़े नियम और मानक लागू करने चाहिए, ताकि वे शिक्षा के उद्देश्यों को प्राथमिकता दें और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिल सके।
3. **संविदा आधारित शिक्षकों के बजाय स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति**: भारत में कई शिक्षण संस्थानों में संविदा आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होती है, जो स्थिरता और निरंतरता में कमी का कारण बनता है। इसलिए, स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए ताकि शिक्षा के स्तर को स्थिर और निरंतर बनाए रखा जा सके। स्थाई शिक्षक न केवल शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हैं, बल्कि छात्रों और संस्थानों के बीच एक मजबूत संबंध भी स्थापित करते हैं।
4. **स्तरीय शोध संस्थानों से कोलैबोरेशन**: अध्यापक शिक्षा में सुधार के लिए स्तरीय शोध संस्थानों से सहयोग करना महत्वपूर्ण है। यह शोध अध्यापन विधियों, शिक्षक प्रशिक्षण, और शिक्षा नीति के सुधार में सहायक हो सकता है। उच्च शिक्षा संस्थानों और शोध केंद्रों को शिक्षकों की प्रशिक्षण प्रक्रिया में शामिल करने से नई विधियों और नवाचारों को लागू किया जा सकता है, जो भविष्य के शिक्षकों की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा।
5. **अवसंरचना सुधार**: अध्यापक शिक्षा संस्थानों की अवसंरचना में सुधार की आवश्यकता है। यह न केवल भौतिक सुविधाओं में सुधार के रूप में होना चाहिए, बल्कि डिजिटल उपकरणों और संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी चाहिए। तकनीकी सुविधाओं से लैस कक्षाएं और स्मार्ट लर्निंग टूल्स शिक्षकों को अधिक प्रभावी तरीके से प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसके साथ ही, कक्षाओं और अध्ययन के लिए बेहतर वातावरण का निर्माण भी किया जाना चाहिए।

BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 3, July-September 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

6. **भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना**: अध्यापक शिक्षा में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े निगरानी तंत्र और पारदर्शी नीतियों की आवश्यकता है। सरकारी और निजी संस्थानों में प्रमाणपत्रों की धांधली, गलत प्रशिक्षण और संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। यदि इन पहलुओं पर नियंत्रण नहीं पाया गया, तो शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
7. **पर्यवेक्षण, जवाबदेही और पारदर्शिता**: अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रभावी पर्यवेक्षण और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रत्येक संस्थान के प्रदर्शन की नियमित निगरानी की जानी चाहिए, और शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा, पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा के सभी पहलुओं में स्पष्टता और निष्पक्षता बनी रहे। पारदर्शिता से यह सुनिश्चित होगा कि संस्थान सही तरीके से कार्य कर रहे हैं और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है।

❖ निष्कर्ष :

भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) कई सकारात्मक पहलुओं का प्रस्ताव करती है, लेकिन इसे लागू करने में चुनौतियां भी हैं। अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य न केवल शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाना है, बल्कि उन्हें समाज में बदलते परिवेश के अनुसार तैयार करना भी है। हालांकि, कई मुद्दों का समाधान अब तक नहीं हो पाया है, जैसे कि गुणवत्तापूर्ण अध्यापक शिक्षा, अवसंरचना की कमी, और भ्रष्टाचार। अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार और शैक्षिक संस्थानों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। वर्तमान में अध्यापक शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता की कमी और भ्रष्टाचार मुख्य समस्याएं हैं, जो शिक्षा के समग्र स्तर को प्रभावित करती हैं। इसके समाधान के लिए, पर्याप्त फंडिंग, स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति, और एकीकृत चार वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, निजीकरण पर नियंत्रण, संस्थानों में सुधार, और पारदर्शिता को बढ़ावा देना भी जरूरी है। अध्यापक शिक्षा में सुधार के लिए शोध संस्थानों से सहयोग और शिक्षक प्रशिक्षण के स्तर को बढ़ाना चाहिए, ताकि शिक्षक समाज के बदलते समय के अनुरूप प्रभावी ढंग से शिक्षा प्रदान कर सकें। यदि इन मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाता है और सुधार योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाता है, तो अध्यापक शिक्षा प्रणाली में उल्लेखनीय परिवर्तन हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप, देश में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा, जिससे छात्र अधिक सक्षम और सशक्त बनेंगे, जो राष्ट्र के समग्र विकास में योगदान देंगे।

BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
issn : 3048-6971
Vol. 2, Issue 3, July-September 2024
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/

संदर्भ:

1. **कुमारी, एस. (2020).** *एनईपी 2020 चैलेंजेज टू टीचर्स एजुकेशन.* इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च, 6(10), 420-424.
2. **स्मिथा, एस. (2020).** *नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) 2020-ऑपर्च्युनिटीज एंड चैलेंजेज इन टीचर एजुकेशन.* इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, 11(11), 1881-1886.
3. **दार, आर.ए., और जान, टी. (2023).** *चेंजिंग रोल ऑफ टीचर एजुकेटर्स इन व्यू ऑफ एनईपी 2020.* जर्नल ऑफ शीआन यूनिवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी, 15(1), 144-156.
4. **मसीह, एम. (2023).** *इननोवेशंस एंड न्यू रिफॉर्म्स इन टीचर एजुकेशन: एडाप्टिंग टू विजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) 2020.* विद्या: ए जर्नल ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी, 2(2), 262-266.
5. **कुमार, आर.** (2020, 21 सितंबर). *क्रियान्वयन में सकारात्मक नियत तय करेगी नई शिक्षा नीति 2020 की सफलता. ऑडीशन टाइम्स,* लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- **वेंकटेश्वरलू, बी. (2021).** *ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ एनईपी 2020: इश्यूज, अप्रोचेस, चैलेंजेज, ऑपर्च्युनिटीज एंड क्रिटिसिज्म.* इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च, 10(2), 191-196.
- **फातिमा, एन., ज़ई, ए.एफ., अख्तर, एस., और चिब, एम. (2023).** *रीशेपिंग टीचर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया थ्रू एनईपी-2020.* टीचर एजुकेशन, 16(2).
- **नंदी, ए., दास, टी., और हलदर, टी. (2022).** *ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ रिकमेंडेशन्स ऑफ एनईपी 2020 टू रिफॉर्म टीचर एजुकेशन इन इंडिया.* एग्पे द रॉयल गोंडवाना रिसर्च जर्नल ऑफ हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस, 3(5), 6-14.
- **दीक्षित, आर.के. (2020).** *नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) 2020-ऑपर्च्युनिटीज एंड चैलेंजेज इन टीचर एजुकेशन.* नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, 120.
- **चक्रदेव, डी.के., और इनामदार, वी.डी.के. (2022)।** *नीड फॉर कम्पलसरी टीचर एजुकेशन कोर्सेज फॉर हायर एजुकेशन फैकल्टी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020.* सुमेधा जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, 11(2), 68-73.
- **कोराडा, एम. (2023)।** *एनईपी-2020: टीचर एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट।* इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च, 12(4), 4.

****